विविध सिविल

समक्ष: *आर. एस. नरूला, सी. जे. और एम. आर. शर्मा जे.*

राम नाथ और एक अन्य, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य, *उत्तरदाता।*

1974 का सी. डब्ल्यू. नं. 1041.

24 जुलाई, 1974।

पंजाब शराब लाइसेंस नियम (1956) (1 अप्रैल, 1967 से प्रभावी रूप से संशोधित) - नियम 36 (17) - भारत का संविधान (1950) - अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) - नियम 36 (17) - क्या अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) - शराब की दुकान की नीलामी - घोषणा नीलामी में बोली अत्यधिक हो गई है - ऐसी घोषणा के बाद नीलामी के पीठासीन अधिकारी - क्या बोली की पूरी राशि का कोई हिस्सा या अंश मांग सकते हैं।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत एक नागरिक के अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध की तर्कसंगतता या अन्यथा के बारे में निर्णय प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के प्रकाश में और लागू कानून की नीति और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और आक्षेपित प्रावधान द्वारा रोका जाने वाला कुचक्र को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। पंजाब शराब लाइसेंस नियम (1956) का नियम 36 (17) भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) के प्रावधानों से परे नहीं है क्योंकि : (1) यह तथ्य कि नीलामी के किसी भी चरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणा के खिलाफ कोई अपील नहीं है कि बोलियां अत्यधिक अधिक हो गई हैं, प्रासंगिक नहीं है क्योंकि वह सार्वजनिक नीलामी आयोजित करते समय किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्य का उपयोग नहीं करता है। एक शराब की दुकान; (2) उत्पाद शुल्क नियम नीलामी के पीठासीन अधिकारी को सफल बोलीदाता के चयन का अंतिम मध्यस्थ नहीं बनाते हैं। नियम 36(22) के तहत, किसी विशेष शराब की दुकान के सफल बोलीदाता की पसंद के बारे में अंतिम निर्णय राज्य में सर्वोच्च आबकारी प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, जो कि आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा नियम 22 (1) के तहत उन्हें दी गई विस्तृत जानकारी के आधार पर और उत्पाद शुल्क अनुबंधों के अपने स्वयं के विशाल और विविध अनुभव की पृष्ठभूमि के आधार पर है। यह अपने आप में नियमों के नियम 36 (17) के परंतुक द्वारा मनमाने तरीके से पीठासीन अधिकारी में निहित शक्ति के प्रयोग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय है; (3) अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) को ऐसे मामले में लागू नहीं किया जा सकता है जहां एक व्यक्ति को किसी विशेष अनुबंध को पूरा करने के लिए दूसरे के बजाय चुना जाता है, जिसके लिए विवेकाधिकार सरकार के पास छोड़ दिया जाना चाहिए। एक अनुबंध जो सरकार से आयोजित किया जाता है, एक निजी पार्टी से आयोजित अनुबंध से अलग नहीं होता है। एक व्यक्ति जिसे अनुबंध नहीं दिया गया है, वह शिकायत नहीं कर सकता है कि किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करने के अधिकार से वंचित किया गया है जैसा कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) द्वारा विचार किया गया है; (4) केवल इसलिए कि एक सांविधिक शक्ति है

विवेकाधीन, इसे आवश्यक रूप से भेदभावपूर्ण नहीं माना जा सकता है; और (5) पीठासीन अधिकारी को प्रदत्त शक्ति को मनमाना नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह केवल तभी होता है जब पीठासीन अधिकारी अपने विवेक से और अपने विशेष ज्ञान और अनुभव के साथ होता है। यह राय बनती है कि बोली लगाने वाले ने अत्यधिक अत्यधिक मुद्रा ग्रहण कर ली है कि वह आक्षेपित शर्त लागू कर सकता है। ऐसे मामलों की परिस्थितियों में यह एक पर्याप्त गाइड-लाइन है।

***यह* अभिनिर्धारित किया गया कि हालांकि पंजाब शराब लाइसेंस नियम, 1956 (यथासंशोधित) के नियम 36 (17) में निहित प्रावधान शराब की दुकानों की नीलामी के पीठासीन अधिकारी पर "पूरी शुल्क बोली" की मांग करने के लिए सार्वजनिक कर्तव्य को दर्शाता है, और मांग को लागू करने का तरीका (मांग पूरी होने तक बोली पर विचार करने से इनकार करके) भी लगभग अनिवार्य भाषा में इंगित किया गया है। फिर भी पूरी राशि जमा करने की आवश्यकता वाला प्रावधान क्या है? फिर भी (क) कोई नियम या कानून परंतुक की आवश्यकताओं के उल्लंघन में आयोजित नीलामी को अमान्य नहीं करता है; (ख) नीलामी करने वालों का पीठासीन अधिकारी पर कोई नियंत्रण नहीं है; और (ग) पत्र का कड़ाई से पालन करने और परंतुक की भावना के अनुरूप न होने से सफल बोलीदाताओं के साथ उस नीलामी में सामान्य अन्याय और असुविधा होने की संभावना है जिस पर नियम के सख्त अनुपालन पर जोर नहीं दिया जाता है। यह नियम, यह प्रावधान करते हुए कि पीठासीन अधिकारी पूरी बोली राशि जमा करने का निर्देश दे सकता है, केवल उस अधिकतम सीमा को इंगित करता है जिस तक जमा को मजबूर किया जा सकता है। अधिनियम की योजना और शराब नियमों को ध्यान में रखते हुए। और राजस्व बढ़ाने और सुरक्षित करने का उद्देश्य। सिद्धांत '*ओम्ने माजस महाद्वीप से माइनस* में' जिसका अर्थ है कि 'अधिक में कम शामिल है' नियम 36 (17) के परंतुक के पहले वाक्य में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति "पूरी राशि बोली" की व्याख्या पर पूरी तरह से लागू होता है। इसलिए यह प्रावधान अधिनियम के तहत नीलामी के पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार देता है कि वह बोली की राशि का पूरा या कोई अंश या कोई हिस्सा मांग सकता है, जो उसके द्वारा यह घोषणा करने के बाद किया जा सकता है कि बोलियां अत्यधिक हो गई हैं।**

***भारत के संविधान के अनुच्छेद* 226 *में अनुरोध किया गया है कि सेक्टर 22, 19 में स्थित देशी शराब की दुकानों के संबंध में आयोजित आक्षेपित नीलामी को रद्द करने के लिए* एक उचित रिट, *आदेश या निर्देश जारी किया जाए* । 28. वर्ष *1974-75 के लिए सेक्टर 22* की भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर *और उक्त लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को रोकना*।**

याचिकाकर्ताओं की ओर से *श्री एचएल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता (मेसर्स एसपी गोयल, एससी सिब्बल और एके जायसवाल, वकील, उनके साथ)।*

जे. एन. कौशल, वरिष्ठ अधिवक्ता और आनंद स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता (उनके साथ अशोक भान), प्रतिवादी *संख्या 10की ओर से।* 1 *से* 3.

प्रतिवादी संख्या 10 *की ओर से तीरथ सिंह मुंजराल, एडवोकेट।* 4.

एम. एल. पुरी, वकील, प्रतिवादी *संख्या 10 के लिए।* 6.

निर्णय

नरूला, सी.जे.- प्रतिवादी 2 और 3 (आबकारी और कराधान आयुक्त, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और कलेक्टर-सह-उप आबकारी और कराधान आयुक्त) द्वारा सेक्टर 19, 22, 28 और 35 में स्थित देशी शराब की दुकानों और सेक्टर 22, चंडीगढ़ के भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर की दुकानों की नीलामी की वैधता और वैधता की वैधता और वैधानिकता। (ख) वित्त वर्ष 1974-75 के लिए प्रतिवादी 4 से 7 में से एक या दूसरे के पक्ष में राम नाथ और केवल कृष्ण द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका में मुख्य रूप से दो आधारों पर चुनौती दी गई है, अर्थात् :-

1. पंजाब शराब लाइसेंस नियम, 1956 का नियम 36 (17), जैसा कि 1 अप्रैल, 1967 (इसके बाद शराब नियम कहा जाता है) से संशोधित किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 14 के *विपरीत* है क्योंकि यह नीलामी के पीठासीन अधिकारी को इस मामले में मनमानी, अनिर्देशित और अनिर्देशित शक्तियां प्रदान करता है कि क्या बोली किसी विशेष नीलामी में किसी विशेष चरण में अत्यधिक है या नहीं। ताकि बोली राशि के तत्काल नकद जमा की शर्त को लागू करने को उचित ठहराया जा सके, जो वार्षिक शुल्क की पूरी राशि तक विस्तारित हो सकती है, और यह कि पीठासीन अधिकारी में आक्षेपित नियम द्वारा निहित उक्त शक्ति दमनकारी है और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत याचिकाकर्ताओं के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध के बराबर है; और
2. भले ही उक्त नियम को असंवैधानिक नहीं माना जाता है, शराब की दुकानों की आक्षेपित नीलामी अवैध है, क्योंकि आक्षेपित नीलामी के मामले में उत्तरदाताओं द्वारा लगाई गई तत्काल अग्रिम जमा की शर्त उस नियम की सीमित सीमाओं के अनुरूप और भीतर नहीं थी।

वर्तमान मामले में जिन परिस्थितियों में ये प्रश्न उठे हैं, वे बिल्कुल जटिल नहीं हैं और पहली बार ध्यान दिया जा सकता है।

2. पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 4 1914 (इसके बाद इसे कहा जाता है) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर लागू होता है। विचाराधीन दुकानों की नीलामी वर्ष 1974-75 के लिए की जानी थी। शराब के नियम। याचिकाकर्ता मनीमाजरा और सेक्टर 22 में देशी शराब की दुकानों के मौजूदा लाइसेंसधारी थे। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा 1974-75 के लिए देशी शराब, विदेशी शराब और बीयर की दुकानों की नीलामी के लिए जारी सार्वजनिक नोटिस (अनुबंध पी -1 1) में कहा गया था कि नीलामी रविवार, 3 मार्च, 1974 को सुबह 10.30 बजे एस्टेट कार्यालय, सेक्टर 17, चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी और प्रत्येक बोलीदाता को 25 रुपये जमा करने होंगे। जो सफल बोलीदाताओं की अग्रिम राशि से काटा जाएगा और दूसरों को वापस कर दिया जाएगा। नोटिस में आगे कहा गया था कि सफल बोलीदाता को सात दिनों के भीतर अग्रिम लाइसेंस-शुल्क की राशि जमा करनी होगी, और हालांकि नीलामी की शर्तों का विवरण नीलामी के समय घोषित किया जाना था, बोलीदाताओं को अपने संबंधित क्षेत्रों के तहसीलदारों से या अन्य

सक्षम अधिकारियों से सॉल्वेंसी के प्रमाण पत्र लाने की आवश्यकता थी। रिट याचिका का अनुलग्नक पी-2 नीलामी शर्तों के संबंधित खंडों की एक प्रति है, जिन्हें नीलामी के समय आबकारी अधिकारियों द्वारा घोषित किया गया था। नीलामी की एकमात्र शर्तें जो हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हैं, वे पैराग्राफ 3, 4 (i), 12 (i) में निहित हैं। और (ii) और अनुलग्नक पी. 2 के 30. उन्हें तैयार संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: –

"3. किसी भी लाइसेंस के लिए किसी भी व्यक्ति को बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसने सरकारी खजाने में 25 रुपये की राशि जमा नहीं की है या नीलामी के समय पीठासीन अधिकारी के पास जमा नहीं की है। हालांकि, ऐसा व्यक्ति एक से अधिक लाइसेंस के लिए बोली लगा सकता है।

4.(i) पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम (1914 का 1) की धारा 34 की उप-धारा (2) में यथा निर्धारित, संदिग्ध या अस्वस्थ वित्तीय स्थिति के उच्चतम बोलीदाता को अपने लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी अथवा प्रतिभूति के बदले उचित जमा राशि जमा करनी होगी, जिसे कठोरता से लागू किया जाएगा।

12.(i) सफल बोलीदाता नीलामी की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर वाषक लाइसेंस-शुल्क बोली का दसवां भाग सरकारी खजाने में जमा करेगा और उपर्युक्त राशि उसे वापस नहीं की जाएगी।

(ii) सफल बोलीदाता जिसे देशी शराब की खुदरा दुकान के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है, उसे अप्रैल से शुरू होने वाले प्रत्येक महीने की पंद्रहवीं तारीख तक लगातार दस समान किस्तों में लाइसेंस-शुल्क की शेष राशि का भुगतान करना होगा।

30. विदेशी शराब (एल. 2 और एल. 10) के लाइसेंस के लिए सबसे सफल बोलीदाता को नीलामी के सात दिनों के भीतर वार्षिक लाइसेंस-शुल्क का छठा हिस्सा जमा करना होगा और अप्रैल से शुरू होने वाले प्रत्येक महीने की सात तारीख तक दस समान किस्तों में शेष राशि का भुगतान करना होगा। लाइसेंस-शुल्क का अग्रिम भुगतान करने में विफलता अंतिम बोली की अस्वीकृति होगी और विचाराधीन लाइसेंस को सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा फिर से बेचा जा सकता है और सरकार को राजस्व के किसी भी नुकसान की वसूली चूककर्ता बोलीदाता से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

3. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि जब प्रतिवादी नंबर 4 (मेसर्स किदार नाथ एंड कंपनी) ने सेक्टर 22 में देशी शराब की दुकान के लिए 12,00,000 रुपये के लिए अपनी बोली दी, जबकि कई बोलियां पहले ही दी जा चुकी थीं, तो याचिकाकर्ताओं ने 12,10,000 रुपये की अपनी बोली दी, लेकिन प्रतिवादी नंबर 3 (कलेक्टर) ने अवैध रूप से और मनमाने ढंग से याचिकाकर्ताओं को याचिकाकर्ताओं के समक्ष मौके पर नकद में प्रस्तावित बोली की राशि का छठा हिस्सा जमा करने की आवश्यकता थी। प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। यह भी आरोप लगाया गया है कि हालांकि याचिकाकर्ताओं और कुछ अन्य मौजूदा लाइसेंसधारियों ने कलेक्टर द्वारा जारी अपने सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र दिखाए, और यह भी विरोध किया कि बोली की राशि का छठा हिस्सा जमा करने की आवश्यकता न तो नीलामी नोटिस (अनुबंध पी -1) के अनुसार थी, न ही मौके पर घोषित नीलामी की शर्तों (प्रदर्शनी पी 2) द्वारा उचित थी। उनकी दलील को खारिज कर दिया गया, याचिकाकर्ताओं की बोली पर विचार नहीं किया गया और प्रतिवादी नंबर 4 की निचली बोली को उच्चतम घोषित किया गया। सेक्टर 19, 28, 35 और मनीमाजरा के लाइसेंसधारियों (प्रतिवादी 5 और 7 सहित, जो क्रमशः सेक्टर 19 और 35 के लाइसेंसधारक थे) ने 4 मार्च, 1974 को केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य आयुक्त को एक लिखित अभ्यावेदन (कॉपी अनुलग्नक पी 3) प्रस्तुत किया, जिसमें शिकायत की गई कि सेक्टर 22 में ठेके के लिए प्रतिस्पर्धी बोली को आबकारी अधिकारियों द्वारा एक निश्चित राशि से अधिक की बोली पर प्रतिबंध लगाकर बंद कर दिया गया है। बोली की पूरी रकम का छठा हिस्सा 'हथौड़े के गिरने पर' जमा करना।

4. सेक्टर 22 के ठेके की नीलामी पूरी होने के बाद, सेक्टर 24 के ठेके के लिए बोली आमंत्रित की गई थी, और राज किशन द्वारा दी गई 8,25,000 रुपये की उच्चतम बोली को किसी भी स्तर पर किसी भी बोलीदाता की आवश्यकता के बिना स्वीकार कर लिया गया था। सेक्टर 19 के ठेके की नीलामी के दौरान, तीसरे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित बोली के छठे हिस्से की नकद जमा की शर्त लगाई गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने 10,70,000 रुपये की बोली लगाई थी। उत्तरदाता संख्या 5(मेसर्स जगन नाथ & कं) इसके बाद उस राशि के छठे हिस्से की नकद जमा करने के बाद 11,10,000 रुपये के लिए बोली दी। याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को प्रतिवादी नंबर 3 ने बिना किसी नकद जमा किए अभी भी उच्च बोली की पेशकश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। नकद जमा की शर्त सेक्टर 28 और 35 की दुकानों की नीलामी के मामले में लगाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदाताओं 6 और 7 ने क्रमशः 8,76,000 रुपये की उच्चतम बोली की पेशकश की थी। और 7,00,000 रुपये। क्रमशः, अपेक्षित नकद जमा करने के बाद। सेक्टर 22 में भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर के ठेके की नीलामी के मामले में, प्रस्तावित बोली की एक-चौथाई राशि जमा करने की शर्त लगाई गई थी, और प्रतिवादी नंबर 4 की उच्चतम बोली को मौके पर नकद में इतनी राशि जमा करने पर स्वीकार किया गया था। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे उपरोक्त तीनों दुकानों के मामले में ऊंची बोली लगाने से वंचित रह गए क्योंकि इस शर्त को लागू किया गया था।

5. उपर्युक्त तरीके से मौके पर दी गई उच्चतम बोली प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पुष्टि के अधीन थी। इस तरह की पुष्टि से पहले, याचिकाकर्ताओं ने 5 मार्च, 1974 (अनुबंध पी -4) को प्रतिवादी नंबर 2 को अपना आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने आग्रह किया कि प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा आयोजित विभिन्न दुकानों की नीलामी शून्य थी और शराब नियमों और नीलामी की शर्तों के खिलाफ थी। उस अभ्यावेदन के दौरान याचिकाकर्ताओं ने सेक्टर 22 के ठेके का लाइसेंस 14,01,000 रुपये में प्राप्त करने की पेशकश की, और याचिकाकर्ताओं ने प्रतिनिधित्व के साथ 75,000 रुपये की राशि में एक बैंक ड्राफ्ट और उनके सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र संलग्न किए। याचिकाकर्ताओं के उक्त प्रस्ताव के बावजूद, दूसरे प्रतिवादी ने ऊपर उल्लिखित उत्तरदाताओं की उपरोक्त सभी उच्चतम बोलियों को मंजूरी दे दी। कलेक्टर को बोली की पूरी राशि नकद में जमा करने का निर्देश देने के लिए अधिकृत करने वाले नियम की वैधता पर सवाल उठाने के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया है कि कोई भी नियम कलेक्टर को यह निर्देश देने की अनुमति नहीं देता है कि बोली की राशि का एक-चौथाई या छठा हिस्सा मौके पर जमा किया जाना चाहिए। और जहां तक तीन विवादित नीलामियों के मामले में कलेक्टर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश बोली की पूरी राशि नहीं था, बल्कि उसके द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार तय किया गया एक अंश था, इसलिए इस आदेश को रद्द किया जा सकता है।

6. प्रतिवादी 1 से 3 के विद्वान वकील श्री आनंद स्वरूप ने इसकी विचारणीयता पर दो प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं। याचिका सबसे पहले यह तर्क दिया गया कि दो व्यक्तियों द्वारा यह संयुक्त याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि उन्होंने एक फर्म का गठन नहीं किया है और किसी भी दुकान के लिए कोई संयुक्त बोली नहीं दी है। मैं दो कारणों से इस आपत्ति को सही नहीं ठहरा पा रहा हूं। पहला, दोनों याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने सेक्टर 22 देशी शराब की दुकान (याचिका के पैराग्राफ 7) के लिए अपनी बोली की

पेशकश की है और दोनों का दावा है कि उन्हें 12,10,000 रुपये की अपनी बोली को स्वीकार करने और दर्ज करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। दूसरा, भले ही याचिका को केवल याचिकाकर्ता नंबर 1 द्वारा दायर किया गया माना जाए (किस पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए श्री सिब्बल ने एक स्पष्ट प्रस्ताव दिया है), तो भी मुद्दे के दोनों बिंदुओं पर फैसला करना होगा। दूसरी आपत्ति यह है कि याचिकाकर्ता राम नाथ, हालांकि सेक्टर 22 के ठेके की नीलामी के समय मौजूद थे, उन्होंने सेक्टर 22, 19, 28 और 35 के किसी भी देशी शराब की दुकान के लिए या सेक्टर 22 के भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर की दुकान के लिए कोई बोली नहीं लगाई। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के वकील ने हमें नीलामी के समय तैयार किए गए मूल बोली पत्रक दिखाए हैं, जिनकी प्रतियां उत्तरदाताओं 1 से 3 के लिखित बयान के साथ संलग्न की गई हैं और अनुलग्नक आर. 3/1 से आर. 3/5 तक चिह्नित की गई हैं। यह भी आग्रह किया जाता है कि दूसरे याचिकाकर्ता केवल कृष्ण ने नीलामी की शर्तों की शर्त संख्या 3 के तहत आवश्यक 25 रुपये भी जमा नहीं किए, जिसका पालन किए बिना वह किसी भी दुकान के लिए बोली लगाने के लिए अधिकृत नहीं थे। प्रतिवादी चाहते हैं कि हम इन तथ्यों से यह निष्कर्ष निकालें कि याचिकाकर्ता नंबर 2 या तो नीलामी में मौजूद नहीं था या किसी भी दुकान के लिए बोली लगाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी श्री आनंद स्वरूप द्वारा इस तथ्य पर भी जोर दिया गया है कि राम नाथ याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी दुकान के लिए कोई बोली नहीं लगाने के संबंध में प्रतिवादी 1 से 3 के लिखित बयान में निहित "प्रारंभिक आपत्ति" में आबकारी कलेक्टर के कथनों को उक्त याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी जवाबी हलफनामे में खारिज नहीं किया गया है। यह आगे बताया गया है कि याचिका में भी यह विशेष रूप से आरोप नहीं लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने किसी भी दुकान के लिए कोई बोली दी, यानी सेक्टर 19, 22, 28 और 35 की दुकानें। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हीरा लाई सिब्बल ने इस आपत्ति के जवाब में प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी 1 और 2 द्वारा प्रस्तुत बोली पत्रों में कोई पवित्रता नहीं जुड़ी है, क्योंकि बोलीदाताओं के हस्ताक्षर उनकी संबंधित बोलियों पर प्राप्त नहीं किए जाते हैं, बल्कि केवल उच्चतम या सफल बोलीदाता के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाते हैं। जिसमें हेरफेर किया जा सकता है। यह मामला उन निजी उत्तरदाताओं के साथ मिलीभगत का है, जिन्हें आक्षेपित नीलामी से लाभ हुआ है। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं ने वास्तव में 5 मार्च, 1974 (अनुबंध पृष्ठ 4) को केंद्र शासित प्रदेश के आबकारी और कराधान आयुक्त को आक्षेपित आदेशों के खिलाफ अपना लिखित विरोध प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सेक्टर 22 के देशी शराब की दुकान की फिर से नीलामी का अनुरोध किया। यह विवादित नहीं है कि उन्होंने कम से कम उस पत्र में 14,01,000 रुपये की बोली की पेशकश की, और *भारी राशि के डिमांड ड्राफ्ट के साथ बोली का समर्थन करके अपनी सदाशयता दिखाई। श्री सिब्बल ने चिमन लाई पूर्व एम.एल.ए.* बनाम *हरियाणा राज्य और* दूसरा **1970 वर्तमान कानून जर्नल 442 पृष्ठ 448** (1) *मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय (जो मेरे द्वारा तैयार किया गया था)*

के निम्नलिखित अंश पर भरोसा किया है। बहुत।: –

पीठ ने कहा, "मैं इस स्तर पर मित्तल द्वारा इस याचिका की विचारणीयता और इसमें किसी भी तरह की राहत देने को लेकर उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति का निपटारा कर सकता हूं। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप नहीं लगाया है कि उसकी कोई भी जमीन या उसके पास पट्टे पर ली गई किसी भी जमीन को उन नमकीन क्षेत्रों में शामिल किया गया है, जिनकी नीलामी अधिसूचना के तहत की जानी है। मित्तल ने प्रस्तुत किया कि इस तरह की स्थिति में, याचिकाकर्ता का इस मामले में कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, और वह एक व्यस्त निकाय है, जिसे रिट कार्यवाही में सार्वजनिक रूप से अकादमिक प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता ने नीलामी के लिए मांगे गए किसी भी क्षेत्र में किसी भी हित का दावा नहीं किया है। हालांकि, उन्होंने रिट याचिका के पैराग्राफ 1 में कहा है कि वह साल्टपेटर में व्यापक व्यवसाय कर रहे हैं, और इस आरोप को उत्तरदाताओं द्वारा विशेष रूप से खारिज नहीं किया गया है जो हरियाणा राज्य और उद्योग निदेशक, हरियाणा हैं। साल्टपेट्रे व्यवसाय में लगे व्यक्ति के रूप में, वह निश्चित रूप से नीलामी की वैधता सुनिश्चित करने में रुचि रखता है जिसमें वह भाग लेने में सक्षम हो सकता है। इसलिए, हम मित्तल की प्रारंभिक आपत्ति में कोई बल नहीं पाते हैं और तदनुसार इसे अस्वीकार करते हैं। और तर्क दिया कि यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को आक्षेपित नीलामी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, या उनकी रिट याचिका को उस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि

I. याचिकाकर्ता बहुत लंबे समय से शराब के कारोबार में हैं;

II. याचिकाकर्ता एक से अधिक शराब की दुकानों के आवंटी हैं;

III. पहले याचिकाकर्ता ने विवाद में नीलामी में भाग लेने के लिए निर्धारित शुल्क के कारण 25 रुपये जमा किए थे;

IV. याचिकाकर्ता नीलामी में बोली लगाने में सक्षम होने के लिए आवश्यक सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र से लैस था;

V. कम से कम पहला याचिकाकर्ता निर्विवाद रूप से विवादित नीलामी के समय मौजूद था; और

VI. याचिकाकर्ताओं ने 75,000 रुपये से कम की राशि के डिमांड ड्राफ्ट के साथ अपने

लिखित प्रस्ताव का समर्थन किया था।

श्री सिब्बल के इन सभी तर्कों में बल खोजें और यह मानें कि कम से कम पहला याचिकाकर्ता इस मामले में रुचि रखने वाला व्यक्ति है और वह इस प्रारंभिक आपत्ति के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए इस आधार पर इस रिट याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता।

7. उपर्युक्त निर्देशों को अपनाने और दबाने के अलावा। प्रतिवादी 4 के वकील श्री तीरथ सिंह मुंजराल ने प्रारंभिक प्रकृति के दो अतिरिक्त बिंदु उठाए। सबसे पहले, उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को गैर-उपयुक्त होना चाहिए क्योंकि वे एक भौतिक तथ्य को दबाने के दोषी हैं, अर्थात्, लागू नियम पंजाब में 1966 से और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 1967 से अस्तित्व में है। दूसरे, उन्होंने तर्क दिया कि पहले याचिकाकर्ता को वर्ष 1973-74 से संबंधित अंतिम नीलामी में स्वयं इस नियम के तहत नीलामी के समय नकदी जमा करने की आवश्यकता थी, और उसने उक्त आवश्यकता का अनुपालन किया है और इसका लाभ उठाया है, अब सवाल नहीं कर सकता है। उस नियम की वैधता क्योंकि उसे उसके पूर्वोक्त आचरण द्वारा आक्षेपित नियम की वैधता को चुनौती देने से रोक दिया गया माना जाता है। जिस तारीख से विशेष सांविधिक नियम लागू किया गया है, वह मेरी राय में ऐसा मामला नहीं है, जिसका खुलासा न करना किसी भौतिक तथ्य को दबाने के समान होगा। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को किसी भी तरह के दमन का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है/ न ही श्री मुंजराल की दूसरी अतिरिक्त आपत्ति में कोई बल है कि पिछले वर्ष की नीलामी में पहले याचिकाकर्ता द्वारा उसी शर्त के अनुसार भाग लेना उन्हें इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने से वंचित करता है। इसलिए, उत्तरदाताओं की सभी प्रारंभिक आपत्तियां विफल हो जाती हैं।

8. नियम 1 36(17)यू के चारों ओर पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा निम्नलिखित तर्क ों को बुना गया है: –

> "36 (17) पीठासीन अधिकारी उच्चतम या किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। जब उच्चतम बोली या किसी अन्य बोली को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी ऐसा करने के कारणों को रिकॉर्ड करेगा। वह एक और बोली स्वीकार करने के लिए अपने कारणों को भी दर्ज करेगा। यदि पीठासीन अधिकारी की राय है कि बोली अत्यधिक अधिक है, तो वह घोषणा कर सकता है कि यदि कोई उच्च बोली लगाई जाती है, तो वह बोली की पूरी राशि को तत्काल जमा करने की मांग करेगा। यदि ऐसा कोई आदेश पारित किया गया है, तो बाद की सभी बोलियों को इस शर्त के अधीन माना जाएगा कि डब्ल्यू'होल शुल्क बोली तुरंत जमा की जाएगी।"

9. चूंकि श्री हीरा लाल सिब्बल ने पहले दूसरे मुद्दे पर और बाद में लगाए गए नियम की वैधता के प्रश्न पर बहस की थी, इसलिए मैं उनके तर्कों पर उसी क्रम में चर्चा करूंगा जिस क्रम में वे आगे बढ़े थे। दूसरे मुद्दे को निर्धारण के लिए दो बिंदुओं में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात् (क) क्या बोली की "पूरी राशि" जमा करने का निर्देश देने की आवश्यकता नीलामी के पीठासीन अधिकारी के पास बोली की राशि के किसी भी हिस्से या अंश को जमा करने का आदेश देने के लिए कोई विवेकाधिकार छोड़ती है, या यह इस तरह का कोई विवेकाधिकार नहीं देता है कि यदि किसी जमा का आदेश दिया जाना है तो उसे करना होगा। केवल "बोली की पूरी राशि" का होना चाहिए; और (ख) यदि यह माना जाता है कि यदि पीठासीन अधिकारी की राय है कि बोली अत्यधिक अधिक है, तो उसे केवल पूरी राशि का आदेश देने का अधिकार है

बोली जमा की जा रही है, न कि उसका कोई हिस्सा, आक्षेपित नीलामी केवल इसलिए शून्य पर रखी जा सकती है क्योंकि इन सभी मामलों में पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित बोली राशि जमा करने के आदेश नियम का उल्लंघन थे। वकील का तर्क है कि पीठासीन अधिकारी सरकार का एक प्रतिनिधि है और उसके पास यह तय करने का सीमित विवेक है कि वह किस स्तर पर विचार कर सकता है कि बोलियां अत्यधिक हो गई हैं; लेकिन एक बार जब वह उस राय का हो जाता है, और वह परंतुक को लागू करने का फैसला करता है, तो उसके पास "पूरी राशि बोली" जमा करने का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। यह तर्क दिया गया था कि पीठासीन अधिकारी यह घोषणा कर सकता है या नहीं कर सकता है कि बोलियां अत्यधिक हो गई हैं, लेकिन एक बार जब वह ऐसा करने का विकल्प चुनता है तो उसका विवेकसमाप्त हो जाता है, और परंतुक की शेष आवश्यकता स्वचालित रूप से लागू हो जाती है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पीठासीन अधिकारी के अधिकार के संबंध में "हो सकता है" शब्द का उपयोग यह घोषणा करने के लिए किया जाता है कि वह तत्काल जमा राशि की मांग करेगा, यह "होगा" के संदर्भ में है, और इसे विशेष रूप से इस तरह से समझा जाना चाहिए क्योंकि परंतुक में अंतिम वाक्य में घोषणा के बाद बोली की पूरी राशि जमा किए बिना किसी भी बोली के मनोरंजन के खिलाफ एक स्पष्ट निषेध शामिल है। पीठासीन अधिकारी द्वारा बनाया गया। वकील इस संबंध में पंजाब राज्य बनाम *सत्य पाल डांग और अन्य* (2) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के निम्नलिखित अंश पर भरोसा करते हैं :-

> "यहां संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या अनुच्छेद 199 (4) के प्रावधानों को अनिवार्य या केवल निर्देशिका के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। कानून के अनिवार्य प्रावधान और जो केवल निर्देशिका है, के बीच अंतर यह है कि एक अनिवार्य प्रावधान में किसी अन्य तरीके से कार्य करने के लिए एक निहित निषेध है, जबकि एक निर्देशिका प्रावधान में पर्याप्त अनुपालन को पर्याप्त माना जाता है।

और तर्क देता है कि परंतुक में निहित निषेध व्यक्त है, और न केवल एक निहित है, पीठासीन अधिकारी के लिए परंतुक के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है जो अनिवार्य हैं और केवल निर्देशिका या चर नहीं हैं। में

(2) ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 903.

तथापि, इसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने आगे निम्नानुसार निर्धारित किया है -

> "उन मामलों में जहां सख्त अनुपालन को अधिनियम की वैधता के लिए एक शर्त मिसाल के रूप में इंगित किया जाता है, इसे जारी रखने की उपेक्षा को घातक के रूप में इंगित किया जाता है। लेकिन ऐसे मामलों में जहां एक सार्वजनिक कर्तव्य लगाया जाता है और प्रदर्शन के तरीके को अनिवार्य भाषा में भी इंगित किया जाता है, प्रावधान को आमतौर पर केवल निर्देशिका के रूप में माना जाता है जब दूसरों के साथ सामान्य अन्याय या असुविधा होती है और कर्तव्य का पालन करने वालों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है।

यद्यपि परंतुक पीठासीन अधिकारी पर "संपूर्ण शुल्क बोली" की मांग करने का सार्वजनिक कर्तव्य रखता है, और मांग को लागू करने का तरीका (मांग पूरी होने तक बोली पर विचार करने से इनकार करके) भी लगभग अनिवार्य भाषा में इंगित किया गया है, पूरी राशि जमा करने की आवश्यकता वाला प्रावधान मेरी राय में केवल निर्देशिका है क्योंकि (ए) कोई भी नियम या कानून सरकार की आवश्यकताओं का उल्लंघन करके रखे गए चूषण को अमान्य नहीं करता है। प्रतिबंध; (ख) नीलामी करने वालों का पीठासीन अधिकारी पर कोई नियंत्रण नहीं है; और (ग) पत्र का कड़ाई से पालन करने और परंतुक की भावना के अनुरूप न होने से सफल बोलीदाताओं के साथ उस नीलामी में सामान्य अन्याय और असुविधा होने की संभावना है जिस पर नियम के सख्त अनुपालन पर जोर नहीं दिया जाता है।

10. यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि शराब का न्यूनतम और अधिकतम बिक्री मूल्य ही अधिनियम की धारा 59 के तहत तय किया जा सकता है और वास्तव में तय किया गया है, इसलिए अत्यधिक उच्च बोली देने के परिणामस्वरूप सफल बोलीदाता को आवश्यक रूप से कोई नुकसान होने का सवाल ही नहीं हो सकता है। मामले के इस पहलू का मेरी राय में इस सवाल पर कोई प्रभाव नहीं है कि परंतुक की आवश्यकताएं निर्देशिका या अनिवार्य हैं या नहीं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परंतुक के तहत जिस चरण में घोषणा की जा सकती है, उसे पीठासीन अधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया जाता है, जिसका उपयोग उसे सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष नीलामी की विशिष्ट परिस्थितियों में करना होता है, और यहां तक कि जब वह यह राय बनाता है कि बोली अत्यधिक अधिक है, वह प्रश्न में घोषणा कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। यद्यपि यह स्थापित कानून है कि न तो "हो सकता है" शब्द का उपयोग यह इंगित करता है कि प्रावधान निर्देशिका है, और न ही "होगा" शब्द का उपयोग एक निश्चित की ओर जाता है आवश्यकता अनिवार्य या अनिवार्य होने के बारे में, दो शब्दों के सामान्य अर्थ को प्रभाव दिया जाना चाहिए यदि दोनों शब्द एक-दूसरे के विपरीत अलग-अलग स्थानों पर एक ही प्रावधान में उपयोग किए जाते हैं, और संदर्भ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह इंगित करता हो कि एक शब्द का उपयोग

एक स्थान पर किया गया था और दूसरे का उपयोग केवल टॉटोलॉजी से बचने के लिए किया गया था। "हो सकता है" या "होगा" शब्द की व्याख्या के प्रासंगिक नियमों को उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम *बाबू राम उपाध्याय* (3) में अपने निर्णय के निम्नलिखित पारित में सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप द्वारा संक्षेप में निर्धारित किया गया है ।: –

"जब कोई क़ानून "होगा" शब्द का उपयोग करता है, *प्रत्यक्षतः* यह अनिवार्य है, लेकिन न्यायालय कानून के पूरे दायरे में सावधानीपूर्वक भाग लेकर विधायिका के वास्तविक इरादे का पता लगा सकता है। विधायिका के वास्तविक इरादे का पता लगाने के लिए न्यायालय विचार कर सकता है, *अन्य बातों के साथ-साथ,* संविधि की प्रकृति और डिजाइन, और इसके परिणामस्वरूप होने वाले परिणाम, अन्य प्रावधानों का प्रभाव जिसके तहत विचाराधीन प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता से बचा जाता है, परिस्थिति, अर्थात्, कि संविधि प्रावधानों का अनुपालन न करने की आकस्मिकता का प्रावधान करती है, तथ्य यह है कि प्रावधानों का अनुपालन न करने पर कुछ जुर्माना लगाया जाता है या नहीं, इससे होने वाले गंभीर या तुच्छ परिणाम, और, सबसे बढ़कर, क्या कानून का उद्देश्य पराजित हो जाएगा या आगे बाबू राम उपाध्याय के मामले (सुप्रा) में *सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपर्युक्त अंश में निर्धारित निर्माण के सिद्धांतों को लागू करते हुए* , मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परंतुक के दूसरे वाक्य में निषेध अनिवार्य है; घोषणा करने या न करने के लिए पीठासीन अधिकारी को परंतुक द्वारा प्रदत्त अधिकार निर्देशिका है। इस पृष्ठभूमि में हमें यह देखना होगा कि क्या यह प्रावधान बोली की राशि के एक अंश को जमा करने की अनुमति देता है या नहीं। मेरी राय में "पूरे" में इसका हिस्सा शामिल है और जब परंतुक कहता है कि पीठासीन अधिकारी पूरे के जमा को निर्देशित कर सकता है

बोली राशि में से, यह केवल उस अधिकतम सीमा को इंगित करता है जिस तक जमा को मजबूर किया जा सकता है। *आत्मा राम* बनाम *पंजाब राज्य और अन्य* (4), संविधान के अनुच्छेद 3 i-A में "संपत्ति" शब्द की व्याख्या के संबंध में यह माना गया था कि "संपत्ति" शब्द में "संपत्ति के हिस्से" शामिल हैं। हमारे समक्ष मामले में श्री सिब्बल द्वारा यह तर्क दिया गया था कि यदि इरादा पीठासीन अधिकारी को जमा की जा रही बोली राशि के एक हिस्से या अंश को निर्देशित करने की अनुमति देना था, तो परंतुक में ऐसा कहने से आसान कुछ भी नहीं होता। आत्मा राम के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी तरह के तर्क को निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया गया था : –

"उसी तर्क की एक और शाखा यह थी कि यदि संविधान के निर्माता अनुच्छेद 31-ए के दायरे में न केवल संपूर्ण सम्पदा बल्कि उसके कुछ हिस्सों को भी शामिल करने का इरादा रखते हैं, तो ऐसा शब्दों में कहने के अलावा कुछ भी आसान नहीं होता, और यह कि 'संपत्ति के हिस्सों' के किसी विशेष उल्लेख के अभाव में, हमें उस अनुच्छेद को 'संपत्ति के भागों' को कवर करने

---

(3) ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 751.

के रूप में भी नहीं पढ़ना चाहिए। हमारी राय में इस विवाद में कोई दम नहीं है, क्योंकि उन्हें कानूनी अधिकतम के पूर्ण ज्ञान का श्रेय दिया जाना चाहिए कि 'जितना अधिक होता है, उतना ही कम ' *ओविन माजस महाद्वीप कम होता है'।*

अधिनियम और शराब नियमों की योजना और राजस्व जुटाने और सुरक्षित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मुझे यह निष्कर्ष अपरिहार्य प्रतीत होता है कि नियम 36 (17) के परंतुक के पहले वाक्य में उपयोग किए गए शब्द "*ओम्ने माजस महाद्वीप इन टू माइनस इन*" की व्याख्या पर सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुझाव दिया कि इस तरह का निष्कर्ष सही नहीं होगा क्योंकि यह परंतुक के दूसरे भाग के साथ विरोधाभासी होगा जो घोषणा किए जाने की स्थिति में बोली की पूरी राशि जमा किए बिना किसी भी बोली पर विचार करने पर अनिवार्य रूप से रोक लगाता है। इस तर्क में भ्रम यह है कि वकील चाहता है कि हम परंतुक के दो वाक्यों में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति "पूरी राशि बोली" को दो अलग-अलग तरीकों से समझें। परंतुक के दूसरे वाक्य में प्रयुक्त प्रश्न की अभिव्यक्ति को वही अर्थ दिया जाना चाहिए जो हमारे द्वारा परंतुक के पहले वाक्य में प्रयुक्त उस अभिव्यक्ति का अर्थ निकालकर दिया गया है।

---

(4) ए.आई.आर. 1959 एस.सी.

11. इस स्थिति का सामना करते हुए कि "पूरी राशि बोली" शब्द की शाब्दिक व्याख्या से अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं, श्री सिब्बल ने हमारे सामने अभिव्यक्ति की एक और व्याख्या की। उन्होंने प्रस्तुत किया कि क़ानूनों की व्याख्या के मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के अनुसार कानून के एक अस्पष्ट टुकड़े को अर्थ देने के लिए प्रावधान में कुछ शब्द जोड़ने की अनुमति है। निर्माण के उस नियम का उपयोग करते हुए, श्री सिब्बल ने हमें इस बात के लिए राजी करने का प्रयास किया है कि हम परंतुक के पहले वाक्य में "पूरी राशि" शब्दों के बाद "अतिरिक्त की" शब्द और "शुल्क बोली" शब्दों से पहले शामिल करें। इस प्रकार, परंतुक का प्रासंगिक भाग इस प्रकार होगा:-

> "यदि पीठासीन अधिकारी की राय है कि बोली अत्यधिक है, तो वह घोषणा कर सकता है कि यदि कोई उच्च बोली लगाई जाती है, तो वह अतिरिक्त शुल्क बोली की पूरी राशि तत्काल जमा करने की मांग करेगा।

इस प्रकार इसका अर्थ यह होगा कि जब पीठासीन अधिकारी द्वारा संबंधित घोषणा की जाती है, तो प्रत्येक अनुवर्ती बोलीदाता द्वारा केवल ऐसी राशि नकद में जमा की जानी चाहिए जो घोषणा किए जाने से पहले दी गई उच्चतम बोली से अधिक हो। इस निर्माण को अपनाने से, वकील ने तर्क दिया कि पूरी कठिनाई हल हो जाएगी, क्योंकि (i) बोली की पूरी राशि के किसी भी अंश को मनमाने ढंग से तय करने के लिए पीठासीन अधिकारी में कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ा जाएगा, (ii) राजस्व की सुरक्षा के लिए परंतुक का उद्देश्य भी संतुष्ट होगा क्योंकि घोषणा से पहले अंतिम बोली तक कोई जमा करने की आवश्यकता नहीं थी, और (iii) घोषणा के बाद बोली लगाने वाले व्यक्तियों को केवल इसलिए अधिक नुकसानदेह स्थिति में नहीं रखा जाएगा क्योंकि वे उच्च बोली लगाने की पेशकश कर रहे हैं। जिस तरह से वकील चाहता है कि हम परंतुक को पढ़ें, वह वास्तव में बहुत आकर्षक है और संभवतः प्रावधान के पीछे के इरादे और उद्देश्य को संतुष्ट कर सकता है, लेकिन हमारे लिए इसे बनाने के लिए परंतुक में शब्दों को पेश करना संभव नहीं लगता है जब परंतुक की भाषा में कोई अस्पष्टता नहीं है, और इसका अर्थ स्पष्ट है। यह सरकार पर निर्भर करता है कि क्या इस परंतुक में संशोधन करना अधिक उपयुक्त होगा या नहीं ताकि इसे उसी तरीके से पढ़ा जा सके जिस प्रकार से श्री सिब्बल चाहते हैं कि हम इसमें कोई संशोधन किए बिना इसे पढ़ें। न्यायालय का कार्य यह पता लगाना है कि कानून क्या है न कि यह क्या होना चाहिए। कानून बनाना विधायिका और प्रत्यायोजित विधायी प्राधिकारी का काम है। श्री सिब्बल द्वारा हमारे समक्ष रखा गया प्रस्ताव चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न हो, उसे नियम बनाने वाले प्राधिकारियों के प्रति स्वयं की प्रशंसा करनी होगी, और यह इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है कि वह कानून में थोड़ा और यहां तक कि बेहतरी के लिए भी बदलाव करे।

व्याख्या की कोई प्रक्रिया। अत, मैं यह कहूंगा कि यह परंतुक अधिनियम के अंतर्गत नीलामी के पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार देता है कि वह परंतुक में उल्लिखित घोषणा के बाद की जाने वाली बोली की राशि का पूरा अथवा कोई अंश अथवा कोई भाग मांग सकता है। ऐसा होने के कारण, परंतुक के प्रभाव के संबंध में मेरे द्वारा उल्लिखित दूसरा मुद्दा नहीं उठता क्योंकि पहले निष्कर्ष से अनूठा निष्कर्ष यह है कि उप आबकारी और कराधान आयुक्त, चंडीगढ़, जिन्होंने नीलामी आयोजित की थी, ने परंतुक के तहत अपने अधिकार की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया था। इसलिए, उस आधार पर नीलामी को शून्य पर नहीं रखा जा सकता है।

12. यह मुझे नियम 36(17) के परंतुक की वैधता के प्रश्न पर ले जाता है। इस प्रस्ताव के समर्थन में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दिया गया एकमात्र तर्क यह है कि परंतुक में बोली राशि के अग्रिम जमा करने की शर्त लगाने के लिए कोई उचित आधार नहीं है, और इसलिए, भेदभाव परंतुक के चेहरे पर बड़ा है। श्री सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) के तहत याचिकाकर्ताओं को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है क्योंकि यह पीठासीन अधिकारी को मनमानी, अनिर्देशित और अनिर्देशित शक्ति प्रदान करता है क्योंकि मामले को पीठासीन अधिकारी की राय पर छोड़ दिया गया है कि बोली अत्यधिक है या नहीं। यह प्रस्तुत करने की मांग की गई थी कि नियम में या किसी भी नियम में कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया गया है कि बोली को कब अत्यधिक माना जाना चाहिए। परंतुक में मार्गदर्शन की इस कथित कमी के कारण, परंतुक द्वारा अधिकृत शर्त मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से प्रयोग करने में सक्षम है। वकील ने कहा कि जहां तक प्रावधान पीठासीन अधिकारी को शुल्क बोली की पूरी राशि तत्काल जमा करने की मांग करने के लिए अधिकृत करता है, यह अत्यधिक दमनकारी है और यह शराब के व्यापार को जारी रखने के याचिकाकर्ताओं के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत तर्क के समर्थन में, यह आगे तर्क दिया गया था कि आम जनता का कोई भी हित संभवतः पीठासीन अधिकारी को परंतुक द्वारा प्रदान की गई मनमानी शक्ति से पूरा नहीं किया जा सकता है, और वास्तव में आम जनता के हित को उस शक्ति का उपयोग करके सबसे अच्छा काम किया जा सकता है जिसके तहत पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च होने के बावजूद किसी भी बोली को अस्वीकार करने का हकदार है। दूसरी ओर राज्य के वकील ने तर्क दिया कि नकद जमा की शर्त लगाने की शक्ति न तो मनमानी है और न ही भेदभावपूर्ण है, और पीठासीन अधिकारी को यह देखना होगा कि राशि के लिए बोली की पेशकश करने वाला व्यक्ति कोई लाभ कमाने में सक्षम हो सकता है और जनता को आपूर्ति की जाने वाली शराब की शुद्ध गुणवत्ता भी उसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। लिखित बयान में यह कहा गया है कि लाइसेंसधारक भाग सकते हैं

ऊंची बोली लगाने के बाद किसी भी समय दुकान की फिर से नीलामी की आवश्यकता होती है, और हालांकि पुनर्विक्रय के कारण नुकसान चूककर्ता से वसूल किया जा सकता है, यह वास्तव में शायद ही कभी वसूल किया जाता है क्योंकि उनके नाम पर या तो कोई अचल संपत्ति नहीं है या वे इसे दूसरों के नाम पर स्थानांतरित कर देते हैं। पंजाब राज्य में वर्ष 196869 के लिए देशी शराब की दुकानों से बकाया करोड़ों रुपये के लाइसेंस-शुल्क के बकाया का उल्लेख किया गया है। प्रतिवादियों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि लागू शर्त को लागू करना जनता के हित में है क्योंकि लाइसेंसधारक जो असामान्य रूप से उच्च लाइसेंस-शुल्क पर ठेके प्राप्त करते हैं, वे जनता को मिलावटी सामान बेचकर कदाचार में लिप्त होने की कोशिश करते हैं जो लोगों के जीवन के साथ खेलने के समान है। इन्हीं आधारों पर सरकार ने अपने लिखित वक्तव्य में परंतुक की वैधता और इस प्रकार लगाए गए प्रतिबंध की तर्कसंगतता को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया है।

13. पक्षकारों के वकीलों को सुनने के बाद मैं यह सुविचारित विचार व्यक्त करता हूं कि मेरे द्वारा इसके बाद दिए गए कारणों के लिए श्री सिब्बल द्वारा परंतुक की वैधता के समर्थन में दिए गए किसी भी कथन में कोई बल नहीं है। समिति के पीठासीन अधिकारी! राज्य उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों के पदानुक्रम में एक उच्च अधिकारी होना चाहिए। वर्तमान मामले में प्रतिवादी संख्या 3 जिसने नीलामी आयोजित की थी, वह केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कलेक्टर-सह-उप आबकारी और कराधान आयुक्त हैं। शराब की दुकानों की नीलामी के क्षेत्र में उनके अनुभव के साथ, और किसी विशेष दुकान के निश्चित कोटे के बारे में उनके पास उपलब्ध जानकारी और आंकड़ों के साथ, पिछले वर्षों के दौरान जिस राशि पर यह दिया गया था, उस इलाके की प्रकृति जिसके ठेके को पूरा करना है, और जिस प्रकार की आबादी से दुकान पर ग्राहक बनने की उम्मीद है, वह कला विचार बनाने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति होना चाहिए कि कब किसी विशेष दुकान के लिए बोली अत्यधिक बढ़ गई है। *श्री राम-राम नारायण मेधी* बनाम बॉम्बे राज्य (5) में यह कहा गया था कि राज्य सरकार में बॉम्बे किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम द्वारा अधिकतम क्षेत्र के परिवर्तन की शक्ति और आथक जोत को निहित किया गया है और इसमें विनिदष्ट मानदंडों को ध्यान में रखते हुए इसे व्यक्तिपरक आधार पर छोड़ दिया गया है, राज्य सरकार को इस तरह का विवेकाधिकार प्रदान करने वाला रोम्बे अधिनियम का प्रावधान असंवैधानिक नहीं था। उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया था:

---

(5) ए.आई.आर. 1959 एस.सी. 459.

राम नाथ, आदि केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, आदि।

(नरूला, सी.जे.)

कानिया, सी.जे. *में डॉ. एन. बी. खरे* बनाम *दिल्ली राज्य(* 1950 एस सी: आर 519) (6) जिसमें यह कहा गया था कि इस धारणा के साथ शुरू करना उचित नहीं है कि प्रांतीय सरकार आदेश देते समय अपने कर्तव्य के पालन में संबंधित संविधि के प्रावधानों का दुरुपयोग करेगी, और उस आधार पर क़ानून की वैधता के प्रश्न का निर्णय करेगी। इस बात पर जोर दिया गया कि कानून की वैधता को इसके दुरुपयोग की आशंका के कारण चुनौती नहीं दी जा सकती है। उड़ीसा *राज्य* और *अन्य* बनाम *पुनहरिनारायण जायसवाल और अन्य* (ए: आई आर: 1972 एस: सी: 1816) (7) *में* यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था (एक शराब की दुकान की बिक्री के संबंध में: –

> उन्होंने कहा, 'यह बिक्री राजस्व जुटाने का एक तरीका है। यह मानते हुए कि इस प्रकृति के मामले में मनमानी या अनिर्देशित शक्ति का सवाल उठ सकता है, यह नहीं भूलना चाहिए कि उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति राज्य में सर्वोच्च प्राधिकरण यानी सरकार को दी जाती है जो राज्य के वित्त की रक्षा करने की उम्मीद करती है। ऐसी शक्ति को मनमानी शक्ति नहीं माना जा सकता। यदि उस शक्ति का उपयोग किसी भी संपार्श्विक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो शक्ति का प्रयोग रद्द कर दिया जाएगा।

श्री सिब्बल द्वारा हरि चंद सारदा बनाम *मिजो जिला परिषद और अन्य* (ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 829)(8) *उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा किया* गया। इस आशय के हैं कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत नागरिकों के अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध के प्रमाण का बोझ सरकार पर है, जो याचिकाकर्ताओं के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है। किसी प्रतिबंध की तर्कसंगतता या अन्यथा के बारे में निर्णय प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के आलोक में (जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है) किया जाना है, और लागू कानून की नीति और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और आक्षेपित प्रावधान द्वारा रोकी जाने वाली शरारत को ध्यान में रखते हुए। यह तथ्य कि नीलामी के पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणा के खिलाफ कोई अपील नहीं है, भी अप्रासंगिक है क्योंकि कलेक्टर शराब की दुकान की सार्वजनिक नीलामी करते समय किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्य का उपयोग नहीं कर रहा है।

14. दूसरी बात, उत्पाद शुल्क के नियम नीलामी के पीठासीन अधिकारी को सफल बोलीदाता के चयन का अंतिम मध्यस्थ नहीं बनाता है। नियम 36(17) के शुरुआती भाग से पता चलता है कि पीठासीन अधिकारी उच्चतम बोली को भी स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन उस स्थिति में उसे आबकारी और कराधान आयुक्त को मामले की रिपोर्ट करनी होगी।

नियम 36 (22) जो कलेक्टर (नीलामी के पीठासीन अधिकारी) द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है, यह निर्धारित करता है कि: –

"36 (22) (1) कलेक्टर आबकारी आयुक्त को अग्रेषित करेगा: –

(अ) फॉर्म एम-14 और एम-14-ए में दिए गए विवरण में प्रत्येक दुकान के स्थान को दर्शाया गया है, जिसके लिए लाइसेंस की नीलामी की गई है, वर्ष के दौरान संभावित बिक्री (जिसे प्रूफ लीटर में बताया जाएगा), इस नियम के खंड (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम शुल्क, लाइसेंसों का नाम और पिछले वर्ष की तुलना में लाइसेंस की नीलामी की गई राशि;

(आ) उन मामलों को दर्शाने वाला विवरण जिनमें लाइसेंस की नीलामी उच्चतम बोली के लिए नहीं की गई है, और उच्चतम बोली को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं।

{2} यदि इसके विपरीत कोई सूचना तीन सप्ताह के भीतर या 28 मार्च तक या उससे पहले, जो भी पहले हो, प्राप्त होती है, तो कलेक्टर यह मान सकता है कि आबकारी आयुक्त ने उसके प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। आबकारी और कराधान अधिकारी लाइसेंस और उनके द्वारा प्राप्त दुकानों की एक सूची अग्रेषित करेगा। जिले के पुलिस अधीक्षक, और पंजाब/हरियाणा में लाइसेंस प्राप्त सभी डिस्टिलरी के प्रबंधकों को।

उपर्युक्त नियम से पता चलता है कि किसी विशेष शराब की दुकान के सफल बोलीदाता के चोरी के बारे में अंतिम निर्णय राज्य के सर्वोच्च आबकारी प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, जो कि आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा उप-नियम 22 (1) के तहत उन्हें दी गई विस्तृत जानकारी के आधार पर और अपने स्वयं के बैक-ग्राउंड के साथ है।उत्पाद शुल्क अनुबंधों का विशाल और विविध अनुभव। नियम 36 (22) का उप-नियम (2) आबकारी और कराधान आयुक्त (जो चंडीगढ़ के मामले में केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य आयुक्त है) को नीलामी के पीठासीन अधिकारी की सिफारिश को स्वीकार करने या न करने के लिए अधिकृत करता है । शराब कॉन ट्रैक्टरों को कठिनाई और अनिश्चितता से बचाने के लिए उस उप-नियम में प्रावधान किया गया है कि यदि वह तीन सप्ताह के भीतर प्री साइडिंग अधिकारी द्वारा अनुशंसित उच्चतम बोली या बोलीदाता की पेशकश को अस्वीकार नहीं करता है, तो आबकारी आयुक्त द्वारा नीलामी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। यह अपने आप में इस प्रयोग के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा कवच है; मनमाने ढंग से आक्षेपित परंतुक द्वारा पीठासीन अधिकारी में निहित शक्ति का उल्लंघन।

15.तीसरा, इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा सी. के. *अच्युतन* बनाम *केरल राज्य और अन्य* (ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 490)(9) मामले में अधिकारपूर्वक माना गया है। कि अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) को ऐसे मामले पर लागू नहीं किया जा सकता है जहां एक व्यक्ति को किसी विशेष अनुबंध को पूरा करने के लिए दूसरे के बजाय चुना जाता है, जिसके लिए विवेकाधिकार सरकार के पास छोड़ दिया जाना चाहिए। यह माना गया था कि एक अनुबंध जो सरकार से आयोजित किया जाता है, एक निजी पार्टी से आयोजित अनुबंध से अलग नहीं होता है। एक व्यक्ति जिसे अनुबंध नहीं दिया गया है, वह शिकायत नहीं कर सकता है कि किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करने के अधिकार से वंचित किया गया है जैसा कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) द्वारा विचार किया गया है। *हरिनारायण जायसवाल और अन्य* (सुप्रा) के मामले में इस पहलू पर विस्तार से विचार किया गया है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि यह मामला शराब के ठेके की नीलामी से संबंधित है। इस तथ्य का उल्लेख करने के बाद कि थोक या खुदरा में शराब बेचने के विशेष अधिकार को बेचने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राजस्व जुटाना है, जैसा कि *कूवरजी बी. भरुचा* बनाम *केरल आयुक्त और मुख्य आयुक्त, अजमेर और अन्य* (ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 220)(10)*मामले में सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले में* उनके लॉर्डशिप ने कहा: –

> उन्होंने कहा, 'यह सरकार को तय करना है कि नीलामी में दी गई कीमत पर्याप्त है या नहीं। बोली को स्वीकार या अस्वीकार करते समय, यह केवल एक कार्यकारी कार्य कर रहा है। इसके निष्कर्ष की शुद्धता न्यायिक समीक्षा के लिए खुली नहीं है। हम यह देखने में विफल हैं कि इन मामलों में अनुच्छेद 19 (एल) (जी) या अनुच्छेद 14 के उल्लंघन की दलील कैसे उत्पन्न हो सकती है। धारा 22 में निर्धारित अनन्य विशेषाधिकारों को बेचने की सरकार की शक्ति से इनकार नहीं किया गया था। यह भी विवादित नहीं था कि उन विशेषाधिकारों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जा सकता है। सर्वोत्तम संभव मूल्य प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक नीलामी आयोजित की जाती है। यदि इन पहलुओं को मान्यता दी जाती है, तो यह तर्क देने का कोई आधार नहीं है कि विचाराधीन विशेषाधिकारों के मालिक जिन्होंने उन्हें बेचने की पेशकश की थी, वे उच्चतम बोली को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि प्रस्तावित मूल्य अपर्याप्त है। बोली स्वीकार किए जाने तक कोई संपन्न अनुबंध नहीं है। इससे पहले कि कोई अनुबंध समाप्त हो जाए, बोलीदाताओं के लिए अपनी बोलियां वापस लेने का विकल्प खुला था- देखें *भारत संघ* बनाम *भीमसेन-वलैती राम* ((1970) 2 एससीआर 594 = (एआईआर 1971 एससी 2295))(11)। केवल बोली देकर बोलीदाताओं ने कोई निहित अधिकार हासिल नहीं किया था। तथ्य यह है कि सरकार विक्रेता थी, यह नहीं बदलता है। कानूनी स्थिति एक बार उन विशेषाधिकारों से निपटने के लिए अपने विशेष अधिकार को स्वीकार कर लिया जाता है। यदि सरकार उन विशेषाधिकारों की अनन्य मालिक है, तो अनुच्छेद 19 (एल) (जी) या अनुच्छेद 14 पर निर्भरता अप्रासंगिक हो जाती है। नागरिकों को सरकार से संबंधित संपत्तियों

या अधिकारों में व्यापार करने या व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है - और न ही अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन हो सकता है, अगर सरकार अपने मूल्यवान अधिकारों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य प्राप्त करने की कोशिश करती है। उच्च न्यायालय का यह सोचना पूरी तरह से गलत था कि अधिनियम की धारा 22 और 29 का उद्देश्य राजस्व जुटाना नहीं था। *कूर्जी भरूचा* के मामले (12) (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए अनुसार राजस्व जुटाना ऐसे प्रावधानों के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक था। तथ्य यह है कि देशी शराब की बिक्री से प्राप्त कीमत एक आबकारी राजस्व है, यह अधिकार की प्रकृति को नहीं बदलता है।

हरिनारायण जायसवाल और अन्य (सुप्रा) के मामले *में अपने फैसले में उपरोक्त उद्धृत अंश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को लागू करते हुए* , ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी 4 के विद्वान वकील श्री तीरथ सिंह मुंजराल का तर्क बिना किसी बल के नहीं है कि रिट शराब की दुकान की बिक्री के लिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बातचीत की प्रक्रिया के एक चरण से संबंधित है। और यह कि याचिकाकर्ताओं में सफल बोलीदाता की बोली की स्वीकृति से पहले किसी भी स्तर पर शिकायत करने का कोई निहित अधिकार नहीं था। *हरिनारायण जायसवाल और अन्य (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को फिर से* पुरक्सोटोमा रामानाता क्वेनिम *बनाम मकन कल्याण टंडेल और अन्य* (13) सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले में संदर्भित किया गया था। यह एक शराब की दुकान के निपटान से संबंधित एक और मामला था। वहां फिर से यह कहा गया कि सरकार द्वारा शराब की दुकान की बिक्री के तरीके से संबंधित शर्त संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है, और सरकार के साथ अनुबंध से संबंधित मामलों में, सरकार उस व्यक्ति की निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है जो सबसे अधिक राशि की पेशकश करता है। आगे यह माना गया कि *हरिनारायण जायसवाल और अन्य के* मामले को कुछ वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में तय किए जाने की परिस्थितियों में उस मामले में प्रतिपादित सामान्य सिद्धांतों के बाध्यकारी प्रभाव में कोई कमी नहीं आएगी। *केएन गुरु-स्वामी* बनाम *मैसूर राज्य और अन्य* (14) *उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां* नीति के बारे में और उत्पाद शुल्क अधिनियमों के पीछे का उद्देश्य और सरकार या उसके अधिकारियों की इच्छा से कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करने से बचने की आवश्यकता के बारे में, और आबकारी नियमों की बाध्यकारी प्रकृति को अब ऊपर उल्लिखित उनके लॉर्डशिप के बाद के निर्णयों में निर्धारित कानून के आलोक में और उसके अधीन पढ़ा जाना चाहिए। इस स्थिति में सरकार द्वारा आक्षेपित कार्रवाई के समर्थन में अपने लिखित आदेश में दिए गए कारणों की शुद्धता या अन्यथा पर टिप्पणी करना अनावश्यक है।

12. 1954 एससीआर 873 = (एआईआर 1954 एस.सी., 220)
13. ए.आई.आर. 1974 एस. सी. 651.
14. ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 592.

विवरणी में दिए गए कारणों के अलावा, हरियाणा राज्य के विद्वान महाधिवक्ता श्री जगन नाथ कौशल, जो संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए थे, द्वारा दिए गए कारणों के अलावा, यह था कि परंतुक का उद्देश्य सरकार को बिना किसी कठिनाई के लाइसेंस-शुल्क की वसूली करने में सक्षम बनाना है। उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम *हरिनारायण जायसवाल और अन्य (7)* (सुप्रा), और *पुरक्सोटोमा में रमनाता क्वेंटिन* बनाम *माकन कल्याण टंडेल और अन्य, (*13) (सुप्रा), में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करने के अलावा । श्री कौशल ने श्री संतोष कुमार अग्रवाल बनाम उड़ीसा *राज्य और अन्य* (15) उच्च न्यायालय उड़ीसा की खंडपीठ की टिप्पणियों पर भी भरोसा किया । उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय का कोई विस्तृत संदर्भ देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने केवल *हरिनारायण जायसवाल और अन्य (7)* (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन किया था।

(16) चौथी विधि इस आशय से अच्छी तरह से तय है कि केवल इसलिए कि एक सांविधिक शक्ति विवेकाधीन है, इसे आवश्यक रूप से भेदभावपूर्ण नहीं माना जा सकता है। यदि इस प्रस्ताव के लिए किसी प्राधिकारी की आवश्यकता है, तो इसका संदर्भ *मेसर्स पन्नालाल बिंजराज और अन्य* बनाम *भारत संघ और अन्य* (16), *को दिया जा सकता* है, *श्री राम कृष्ण डालमिया* बनाम *न्यायमूर्ति एस. आर. तेंडोलकर और अन्य* (17), *माताजोग डोबे* बनाम *एच. सी. भरी* (18), *श्री हरीश चंद बनाम अमृतसर के कलेक्टर और एक अन्य* (19) और *अर्जन सिंह बनाम अर्जन सिंह पंजाब राज्य और दूसरा* (20)।

15. ए.आई.आर. 1973 उड़ीसा 217
16. ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 397.
17. ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 538.
18. (1955) 2 एस.सी.आर. 925.
19. ए.आई.आर. 1959 पी.बी. 19' (एफ.बी.)
20. (20) आई.एल.आर. (1960) 2 पी.बी. 645.

17. पांचवां, पीठासीन अधिकारी को प्रदत्त शक्ति को मनमाने के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह केवल तभी होता है जब पीठासीन अधिकारी, अपने ज्ञान और अपने विशेष ज्ञान और अनुभव से, यह राय बनाता है कि बोली लगाने ने अत्यधिक अत्यधिक मुद्रा धारण कर ली है कि वह आक्षेपित शर्त लागू कर सकता है। वर्तमान जैसे मामलों की परिस्थितियों में यह पर्याप्त दिशानिर्देश है।

18. वकील ने हमारे समक्ष किसी अन्य बिंदु पर बहस नहीं की। याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए किसी भी तर्क के सफल होने के बाद, यह रिट याचिका विफल होनी चाहिए और तदनुसार लागत के साथ खारिज की जाती है।

बी.एस.जी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

प्रांशु जैन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
गुरुग्राम, हरियाणा